



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

11/5/97
25/1/97

सं० 20]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 12, 1997/वैशाख 22, 1919

No. 20]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 12, 1997/VAISAKHA 22, 1919

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 1997

सं. एफ. 711-6-1/ई. टी./96.—अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम 1987 (1987 की संख्या 52) की धारा 23 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् एतद्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (नई तकनीकी संस्थाएं खोलने, पाठ्यक्रमों या कार्यक्रमों को शुरू करने तथा पाठ्यक्रमों या कार्यक्रमों में प्रवेशार्थी संख्या हेतु अनुमोदन विनियम), 1994 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

1. (1) इन विनियमों का अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (नई तकनीकी संस्थाएं खोलने, पाठ्यक्रमों या कार्यक्रमों को शुरू करने तथा पाठ्यक्रमों या कार्यक्रमों में प्रवेशार्थी संख्या हेतु अनुमोदन) संशोधन विनियम, 1997 कहा जाए।
(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (नई तकनीकी संस्थाएं खोलने, पाठ्यक्रमों या कार्यक्रमों को शुरू करने तथा पाठ्यक्रमों या कार्यक्रमों में प्रवेशार्थी संख्या हेतु अनुमोदन) विनियम, 1994 में (इसमें इसके पश्चात् संदर्भित कथित विनियम) विनियम 2 को इसके उपविनियम (1) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाए और उपविनियम (1) के रूप में पुनः संख्यांकित होने के बाद निम्नलिखित उपविनियम सम्मिलित किया जाए :

“ये विनियम व्यवसाय प्रशासन निष्णात (एम. बी. ए.) या समकक्ष और कंप्यूटर अनुप्रयोग निष्णात (एम. सी. ए.) या समकक्ष नामक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों और तकनीकी शिक्षा क्षेत्र संबंधी सभी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के प्रस्तावों पर लागू नहीं होंगे”

3. कथित विनियमों में :—

(क) विनियम 3,—

(1) खंड (ख) के लिए निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :

“(ख) ब्यूरो अ. भा. म ” का अर्थ है परिषद् का अखिल भारतीय अध्ययन मंडल ब्यूरो;

(ii) खंड (घ) और (ङ) के लिए निम्नलिखित खंडों को प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“(घ) ब्यूरो अनु. वि. उ. अ.” का अर्थ है परिषद् का अनुसंधान, विकास और उद्योग अन्योन्यक्रिया ब्यूरो ;

“(ङ) ब्यूरो इं. प्रौ.” का अर्थ है परिषद् का इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी ब्यूरो ;

- (ख) अभिव्यक्तियाँ "ब्यूरो अ. मं.", "ब्यूरो मा. प्र." और "ब्यूरो क्षे. स." जहाँ पर भी आएँ वहाँ क्रमशः अभिव्यक्तियाँ "ब्यूरो अ. भा. म.", "ब्यूरो अनु. वि. उ. अ.", "ब्यूरो ह. प्रौ." प्रतिस्थापित की जाएँ।
4. कथित विनियमों में, विनियम 4 में, उपविनियम (2) में, खंड (ii) में, शब्द "व्यावसायिक कालेजों के बारे में" निकाल दिए जाएँ।
5. कथित विनियमों में, विनियम 5 में—
- (क) उपविनियम (1) में,
- (i) शुरू के शब्दों "फार्म आवेदन-पत्र" के लिए शब्द "आवेदन-पत्रों के फार्म" प्रतिस्थापित किए जाएँ।
- (ii) शब्द "पाठ्यक्रमों की जगहें" के बाद शब्द "या व्यवहार्यता का पत्र प्राप्त करने के लिए" जोड़े जाएँ।
- (ख) उपविनियम (2) में, पैरा (ड) के बाद, निम्नलिखित पैरा जोड़ा जाए, अर्थात् :
- "(च) नई तकनीकी संस्था खोलने के लिए परिषद् से व्यवहार्यता पत्र प्राप्त करने का आवेदन फार्म VI में किया जाएगा।"
6. कथित विनियमों में, विनियम 7 में, उपविनियम (1) के लिए निम्नलिखित उपविनियम प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्
- "(1) परिषद् के अनुमोदन के लिए हर आवेदन-पत्र तीन प्रतियों में प्रस्तुत किया जाए और इस आवेदन-पत्र की एक-एक प्रति विनियमों के उपबंधों के अनुसार संबंधित अधिकरणों को भेजी जाए।"
7. कथित विनियमों में, विनियम 8 और 9 के लिए निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—
8. आवेदन-पत्रों की जाँच :
- (1) व्यवहार्यता पत्र प्राप्ति के लिए परिषद् को प्रस्तुत आवेदन-पत्र के मिल जाने पर, संबंधित विश्वविद्यालय या तकनीकी शिक्षा निदेशालय जिसके कार्यक्षेत्र में खोली जाने वाली तकनीकी संस्था आती है, आवेदन-पत्र में उपलब्ध सूचना की जाँच और सत्यापन की व्यवस्था करेगा।
- (2) यदि विश्वविद्यालय या तकनीकी शिक्षा निदेशालय, जैसी भी स्थिति हो, जगह का स्थानीय निरीक्षण करना चाहता है तो वह अपनी स्थानीय निरीक्षण समिति गठित कर सकता है और आवेदक को सूचित करते हुए जगह का निरीक्षण कर सकता है।
- (3) स्थानीय निरीक्षण समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर या विश्वविद्यालय या तकनीकी शिक्षा निदेशालय द्वारा, जैसी स्थिति हो या अन्य माध्यमों से जैसा वह उचित समझे, आवेदन-पत्र में दी गई सूचना के सत्यापन से संतुष्ट हो जाने के बाद, वह संबंधित राज्य सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अपनी सिफारिशें देगा और उसकी प्रति परिषद् को भी भेजेगा।
- (4) विश्वविद्यालय या तकनीकी शिक्षा निदेशालय से, जैसी भी स्थिति हो, सिफारिशों सहित रिपोर्ट प्राप्त होने पर, उपविनियम (3) के तहत, राज्य सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जैसी भी स्थिति हो, परिषद् को रिपोर्ट और सिफारिशें भेजेगा जिनमें निम्नलिखित आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्ताव की व्यवहार्यता का विशेष रूप से उल्लेख होगा :
- (क) अपेक्षित भूमि :
- आवेदक नई तकनीकी संस्था खोलने के लिए उचित भूमि का पता लगाएगा। अपेक्षित न्यूनतम भूमि नीचे दर्शायी गई सारणी-1 के अनुरूप होगी।

सारणी I

क्र. सं.	स्थान	अपेक्षित न्यूनतम भूमि (इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी)
(1)	(2)	(3)
		<u>डिग्री स्तरीय संस्था</u>
		<u>डिप्लोमा स्तरीय संस्था</u>
1.	ग्रामीण क्षेत्र	10 हैक्टेयर
		8 हैक्टेयर
2.	ताल्लुका या जिला मुख्यालय	4 हैक्टेयर
		4 हैक्टेयर
3.	महानगरीय शहर/राज्य राजधानियाँ	2 हैक्टेयर
		2 हैक्टेयर

टिप्पणी :

आवेदक के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वह फार्म VI में आवेदन करते समय उस भूमि पर स्वामित्व या हक रखे जिसे वह प्रस्तावित नई तकनीकी संस्था खोलने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। व्यवहार्यता पत्र के जारी होने के बाद ही स्वामित्व या हक अपेक्षित होगा।

(ख) निधियाँ

(1) किसी पंजीकृत सोसाइटी/न्यास द्वारा नई तकनीकी संस्था खोलने के लिए निधियों की न्यूनतम आवश्यकता निम्न सारणी II के विवरण के अनुरूप होगी :

सारणी II

क्र. सं.	इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी संस्थाओं का अपेक्षित स्तर	न्यूनतम निधि
(1)	(2)	(3)
1.	डिग्री	रु. 50.00 लाख
2.	डिप्लोमा	रु. 25.00 लाख

टिप्पणी :

फार्म VI में आवेदन देते समय यह आवश्यक नहीं होगा कि आवेदक सोसाइटी/न्यास और संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी संयुक्त नाम में बैंक से किसी प्रकार की मियादी जमा राशि रसीद प्रस्तुत करे।

(ग) खंड (क) और (ख) में किसी बात के होते हुए भी, वास्तुकला, होटल प्रबंध और खानपान प्रौद्योगिकी, भेषजी और अनुप्रयुक्त कलाओं और शिल्पों में नई संस्थाएं खोलने के बारे में भूमि की अपेक्षा और निधियां परिषद् द्वारा निर्धारित मानक और मानदंडों के अनुरूप होंगी।

(घ) ट्रैक रिकार्ड : जहां पर सोसाइटी या न्यास पंजीकृत है, वहां पर उसका शैक्षिक संस्था चलाने का कम-से-कम पांच वर्ष का अच्छा ट्रैक रिकार्ड होना चाहिए।

(5) परिषद् को 31 दिसंबर या उससे पहले प्रस्तुत हर आवेदन-पत्र के बारे में संबंधित अधिकरण अर्थात् राज्य सरकार, विश्वविद्यालय या तकनीकी शिक्षा निदेशालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यथाशीघ्र अपनी सिफारिशों परिषद् को भेजने का प्रयास करेंगे ताकि वह 28 फरवरी के बाद आवेदन-पत्रों का प्रक्रमण कर सके।

(6) उपविनियम 9 के उपबंधों के अधीन क्षेत्रीय समिति या अध्ययन मंडल, जैसी स्थिति हो, विभिन्न प्रस्तावों की स्थिति और उन पर राज्य सरकार, विश्वविद्यालय या तकनीकी शिक्षा निदेशालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों पर विचार-विमर्श करेगा और परिषद् को 31 मार्च तक अपनी सिफारिशें देगा।

(7) संबंधित अधिकरणों की सिफारिशों पर विचार करने के बाद और ऐसी आवश्यक पूछताछ, जिसे वह ठीक समझे, परिषद् 15 अप्रैल तक—

- आवेदक को प्रस्ताव संबंधी व्यवहार्यता पत्र जारी करे जिसमें उल्लेख हो कि प्रस्ताव व्यवहार्य है और आवेदक परिषद् का अंतिम अनुमोदन प्राप्त करने के लिए इन विनियमों के तहत आगे की कार्यवाई करे ; या
- आवेदक को खेद पत्र जारी करे और जिस आधार पर या कारणों की वजह से आवेदन-पत्र अस्वीकृत किया गया है, उन्हें बताया जाए :

कोई भी आवेदन-पत्र जब तक अस्वीकृत नहीं किया जाएगा जब तक कि आवेदक को अपनी बात सुनाने का पूरा मौका नहीं दिया जाता।

(8) व्यवहार्यता पत्र : उपविनियम (4) के तहत व्यवहार्यता पत्र जारी करते हुए परिषद् आवेदक को 15 मई तक निम्नलिखित दस्तावेज फार्म 1 में दिए गए आवेदन के साथ प्रस्तुत करने के लिए कहेगी, अर्थात्

- (क) नई संस्थाएं स्थापना हेतु अंकित भूमि संबंधी आवेदक सोसाइटी/न्यास का स्वामित्व/हक के बारे में भूमि के पंजीकरण का विलेख।
- (ख) संबंधित प्राधिकारी से भूमि उपयोग प्रमाण-पत्र।
- (ग) यदि आवेदक उसी प्रांगण में कोई अन्य शैक्षिक संस्था चला रहा है, जहां पर कि नई संस्था स्थापित करने का प्रस्ताव है, उस हालत में आवेदक से एक अटल संकल्प चाहिए होगा कि प्रस्तावित संस्था के लिए प्रांगण में पर्याप्त क्षेत्र विशेष रूप से अंकित किया गया है।
- (ii) सारणी II के अनुसार सोसाइटी/न्यास और संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्रीय अधिकारी के संयुक्त नाम में मियादी जमा राशि दस वर्ष के लिए रखनी होगी, जिसके पश्चात् आवेदक उस राशि को संस्था के विकास कार्य में उपयोग के लिए आवेदन-पत्र दे सकेगा।
- (iii) क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा निधि का हिसाब-किताब रखा जाएगा।
- (iv) यदि आवेदक सोसाइटी/न्यास भूमि पर स्वामित्व का अधिकार नहीं रखता है तो उस हालत में सोसाइटी/न्यास के नाम से पट्टानामा अनुबंध अपेक्षित है जिसमें कम से कम दो वर्ष की अवधि के लिए अस्थाई स्थान के साथ-साथ प्रांगण का नक्शा और चित्र उपलब्ध हों।
- (v) समस्त संस्थागत परिसर के लिए एक मास्टर प्लान जिसके कुर्सी क्षेत्रफल के विवरण में शामिल हों प्रयोगशालाओं, कक्षाओं, डाइंग हॉलों, कार्याशालाओं, पुस्तकालय, प्रशासन खंड, होस्टल आदि का क्षेत्र और साथ ही अनुमानित निर्माण लागत दर्शाते हुए निर्माण विवरण भी प्रस्तुत किया जाए।
- (vi) एक पंजीकृत स्टांपित पत्र पर बचनबंध जिसमें यह उल्लेख हो कि संस्थान परिषद् द्वारा निर्धारित सभी विनियमों, मानदंडों, मार्गदर्शी सिद्धांतों और मानकों का पालन करेगा।

9. नए पाठ्यक्रमों या कार्यक्रमों को शुरू करने या परिपद द्वारा अनुमोदित किसी संस्था की प्रवेशार्थी संख्या में वृद्धि करने से संबंधित आवेदन-पत्रों के बारे में आधार और अनुदेशी सुविधाओं की अतिरिक्त आवश्यकताओं की सूचना 15 मई तक प्रस्तुत की जानी होगी।
10. परिपद द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति आवेदक के खर्चे पर, जैसी स्थिति हो, प्रस्तावित संस्था द्वारा दिए गए सभी विवरणों का सत्यापन करेगी।
11. विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट तथा अन्य प्रासंगिक सूचना परिपद द्वारा कार्यकारिणी समिति के ममक्ष निर्णायार्थ रखी जाएगी।
12. उपविनियम (8) के उपबंधों के अधीन परिपद का अंतिम निर्णय संबंधित राज्य सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय या संबंधित तकनीकी शिक्षा निदेशालय, जैसी स्थिति हो, संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय और आवेदक को 15 जून तक सूचित किया जाएगा अगर आवेदन-पत्र विगत 31 दिसंबर से पहले दिया गया था।
13. आवेदन-पत्र की अस्वीकृति आवेदक को नए सिरे से आगामी शिक्षा वर्ष में आवेदन देने के लिए बंचित नहीं करेगी।
14. परिपद हर वर्ष 31 दिसंबर से पहले अनुमोदित तकनीकी संस्थाओं, विश्वविद्यालय विभागों या समविश्वविद्यालयों के नाम, जो तकनीकी शिक्षा में पाठ्यक्रमों का संचालन कर रहे हैं, परिपद द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम और कार्यक्रम तथा स्वीकृत जगहों की संख्या (वार्षिक प्रवेशार्थी संख्या) प्रकाशित करेगी। यह प्रकाशन कार्य परिपद प्रत्येक पाठ्यक्रम या कार्यक्रम के लिए करेगी और संबंधित प्राधिकारियों को इसके प्रासंगिक उद्घरण भी सूचित करेगी।
15. उपविनियम (9) के तहत सूची के प्रकाशन के बाद अनुमोदित सभी संस्थाओं, पाठ्यक्रमों और जगहों की संख्या को प्रासंगिक सूची में सम्मिलित माना जाएगा।
16. अनुमोदित प्रस्तावों के प्रक्रमण की समय सारणी और क्रम वही रहेगा जो इन विनियमों की संलग्न सारणी में दिए गए हैं। किसी भी प्रकार के आवेदन-पत्र की समय सारणी में परिवर्तन हेतु परिपद को उचित और पर्याप्त कारण लिखित रूप में दर्ज करने होंगे। निकायों द्वारा आवेदन-पत्रों का प्रक्रमण :—

(i) परिपद निम्नलिखित निकायों के माध्यम से विनियमों के अंतर्गत प्राप्त विभिन्न आवेदन-पत्रों को प्रक्रमित करेगी।

(क) संबंधित क्षेत्रीय समिति

(ख) संबंधित अध्ययन मंडल

(ii) आवेदन-पत्र पर अपनी सिफारिश देने से पूर्व क्षेत्रीय समिति या अध्ययन मंडल, जैसी स्थिति हो, तकनीकी शिक्षा को देख रहे राज्य सरकार के सचिव और राज्य सरकार के तकनीकी शिक्षा निदेशक, कुलपति, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के निदेशक, कार्यकारिणी समिति के सदस्य, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिनिधि, अध्यक्ष द्वारा नामित विशेषज्ञ सदस्य, सलाहकार ब्यूरो इंजीनियरी व प्रौद्योगिकी, सलाहकार ब्यूरो अखिल भारतीय अध्ययन मंडल, सलाहकार ब्यूरो जनशक्ति नियोजन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तकनीकी ब्यूरो के प्रतिनिधि और कोई अन्य विशेष आमंत्रित के साथ बैठक करेंगे।

9क. केंद्रीय सरकार को विवरणियाँ : परिपद केंद्रीय सरकार को त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट भेजेगी जिसमें इन विनियमों के साथ संलग्न सारणी के स्तम्भ "3" में दर्शाई गई अंतिम तिथियों के अनुसार परिपद का प्रगति विवरण उपलब्ध रहेगा।

8. कथित विनियमों में, सारणी के लिए निम्नलिखित सारणी प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

सारणी

[देखिए विनियम 8 (12)]

अनुमोदन के लिए आवेदन-पत्रों के प्रक्रमण की समय सारणी और क्रम

क्रम सं.	प्रक्रमण का चरण	प्रक्रमण-कार्य पूरा करने की अंतिम तिथि
(1)	(2)	(3)
1	परिपद के अभ्यर्थापन मुख्यालय, राज्य सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय, तकनीकी शिक्षा निदेशक और क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा प्रस्ताव प्राप्त करना।	31 दिसंबर
2	(i) राज्य सरकार (ii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (iii) विश्वविद्यालय या राज्य मंडल/तकनीकी शिक्षा निदेशक से टिप्पणियाँ प्राप्त करना।	28 फरवरी

(1)	(2)	(3)
3.	राज्य सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय या राज्य तकनीकी शिक्षा निदेशालय से क्षेत्रीय समिति या संबंधित अध्ययन मंडल के विचारार्थ टिप्पणियाँ प्राप्त करना।	31 मार्च
4.	व्यवहार्यता-पत्र जारी करने के लिए	15 अप्रैल
5.	व्यवहार्यता-पत्र के अनुसार आवेदकों से विस्तृत प्रस्ताव और दस्तावेज प्राप्त करना।	31 मई
6.	परिषद् विशेषज्ञ समिति का निरीक्षण और कार्यकारिणी समिति को रिपोर्ट करना और तकनीकी शिक्षा निदेशक, आवेदक, विश्वविद्यालय या तकनीकी शिक्षा निदेशक और क्षेत्रीय कार्यालय को सूचित करते हुए राज्य सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अंतिम निर्णय संप्रेषित करना।	15 जून

9. कथित विनियमों में, फार्म 1 में, शीर्षक "इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी/वास्तुकला, भेषजी, अनुप्रयुक्त कला आदि के अंतर्गत डिग्री/डिप्लोमा संस्थाओं की स्थापना के लिए प्रस्तावों को प्रस्तुत करने हेतु अनुदेश" के नीचे पैरा 1 में, उप-पैरा (क), में अंक, अक्षर और शब्द "31 दिसंबर" के लिए अंक, अक्षर और शब्द "15 मई, व्यवहार्यता पत्र जारी करने के बाद" प्रतिस्थापित किए जाएं।

10. कथित विनियमों में, फार्मों I से U में,

(i) "सात प्रतियाँ" शब्दों के लिए जहाँ भी ये आते हैं "तीन प्रतियाँ" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएं।

(ii) शीर्षक "शासी निकाय के अध्यक्ष की नियुक्ति" के नीचे शब्द "सोसाइटी/न्यास का सदस्य है" हटा दिए जाएं।

11. कथित विनियमों में फार्म V के बाद निम्नलिखित फार्म जोड़ दिया जाए, अर्थात्।

फार्म VI

[(देखिए विनियम 5 (2) (च)]

डिग्री/डिप्लोमा स्तर पर नई तकनीकी संस्था खोलने के लिए व्यवहार्यता पत्र जारी करने हेतु आवेदन-पत्र कृपया संलग्न आवेदन-पत्रों के प्रक्रमण हेतु समय सारणी और प्रक्रिया का अवलोकन करें।

- आवेदक का नाम और पता (पिन कोड सहित)
(न्यास/सोसाइटी/सरकार/विश्वविद्यालय/संस्था)
फैक्स नं.
एस. टी. डी. कोड
आवेदक का सोसाइटी/न्यास के रूप में पंजीकरण सं. और
पंजीकरण की तारीख
सदस्यों/न्यासों का विवरण और उनका शैक्षिक/व्यावसायिक
संस्थाओं को चलाने का अनुभव
प्रस्तावित संस्था का नाम और पता (पिन कोड सहित)
(स्पष्ट रूप से बताइए कि क्या प्रस्तावित जगह ताल्लुका/जिला मुख्यालय/
महानगरीय शहर/राज्य राजधानी/अन्य के अंतर्गत आती है)
- तकनीकी संस्था का प्रकार (सरकारी/प्राइवेट/ विश्वविद्यालय,
आदि) जिसे खोला जाना है।
- संबंधन निकाय का नाम और पता
(विश्वविद्यालय/राज्य मंडल)
- शैक्षिक कार्यक्रम जो शिक्षा वर्ष 19 — 19 से चलाए जाने का प्रस्ताव है।
पाठ्यक्रम शीर्षक अवधि प्रवेश स्तर डिग्री या डिप्लोमा प्रवेशार्थी संख्या

8. आवेदक का ट्रेक रिकार्ड : न्यास/सोसाइटी द्वारा संचालित/प्रबंधित तकनीकी/गैर-व्यावसायिक/व्यावसायिक संस्थाएं
(सरकारी/विश्वविद्यालय पर यह लागू नहीं है) (केवल सोसाइटी/न्यास के लिए)

संस्था का नाम और पता	संचालित पाठ्यक्रम हर पाठ्यक्रम की अवधि	अध्ययन का स्तर	प्रवेशार्थी क्षमता	शुरू करने का वर्ष	क्या अभातशिप/ विश्वविद्यालय/राज्य सरकार/मंडल द्वारा अनुमोदित है
-------------------------	--	-------------------	--------------------	----------------------	--

9. भूमि क्षेत्रफल :

- (क) क्या आवेदक न्यास/सोसाइटी संस्थान द्वारा स्वामित्व प्राप्त है
या पट्टे के आधार पर है स्वामित्व है/नहीं
पट्टा है/नहीं
- (ख) न्यास/सोसाइटी/संस्थान द्वारा खरीद के लिए प्रस्तावित भूमि
क्षेत्र है/नहीं

10. क्या आवेदक न्यास/सोसाइटी/संस्था ने प्रस्ताव की प्रति निम्नलिखित
को भी प्रस्तुत की :

- (क) केंद्रीय या संबंधित राज्य सरकार हां/नहीं
- (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग हां/नहीं
- (ग) विश्वविद्यालय/मंडल हां/नहीं
- (घ) परिषद् का क्षेत्रीय कार्यालय हां/नहीं

11. निधियों की उपलब्धता

(केवल प्रतियां संलग्न करें या प्रासंगिक प्रमाण)

- (क) मियादी जमाशियों रु. लाख
- (ख) बैंक में उपलब्ध निधियां रु. लाख
- (ग) अतिरिक्त निधियों का जुटाव रु. लाख
- (घ) वार्षिक आवर्ती व्यय के चुकाने के लिए निधियां

12. स्थायी आधार पर निर्मित जगह (वर्गमीटर में) की उपलब्धता

13. स्थायी भवन बनने तक अस्थायी आधार पर निर्मित जगह (वर्गमीटर में)
की उपलब्धता।

14. क्या आवेदक ने पहले कभी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् को आवेदन
दिया ? यदि हां, तो कब और प्रस्ताव की अस्वीकृति का कारण ?

15. अन्य कोई सूचना जिसे सोसाइटी/न्यास प्रस्ताव के समर्थन में प्रस्तुत करना चाहे।

घोषणा

मैं/हम की ओर से परिषद् के मानदंडों और मापकों और विनियमों के पालन करने का
वचन देते हैं। मैं व्यवहार्यता पत्र प्राप्ति के बाद निर्धारित अवधि में निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने का भी वचन देता हूँ, नहीं तो हमारे न्यास/सोसाइटी
के प्रस्ताव को परिषद् द्वारा अस्वीकृत करार दिया जाए।

- (1) सोसाइटी/न्यास के नाम अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार भूमि।
- (2) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के मानदंडों के अनुसार आवेदक और संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी के संयुक्त नाम में मियादी जमाशियां रसीदें।
- (3) अनुमानित व्यय के साथ प्रस्तावित संस्था के स्थायी निर्माण के लिए मास्टर प्लान।
- (4) न्यास/सोसाइटी के नाम में अभातशिप के मानदंडों के अनुसार पर्याप्त क्षेत्र वाली अस्थायी जगह का पट्टा दस्तावेज।
- (5) अन्य कोई दस्तावेज जिसे अभातशिप प्रस्ताव के प्रक्रमण हेतु माँग करे।

जगह :

दिनांक :

(न्यास/सोसाइटी के अध्यक्ष/सचिव/न्यासी/अधिकृत
हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर)''

(मोहर)

प्रो. जे. पी. गुप्ता, सदस्य-सचिव

पाद-टिप्पणी:—अधिसूचना सं. एफ. 304-4/सी. सी. एफ./आर. ई. जी./94 दिनांक : 31-10-94 के अनुसार मूल विनियम भारत के राजपत्र, भाग III,
खंड 4 दिनांक : 23 नवंबर, 1994 को प्रकाशित किए गए।**ALL INDIA COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION****NOTIFICATION**

New Delhi, the 11th April, 1997

No. F. 711-6-1/ET/96 :—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 23 of the All India Council for Technical Education Act, 1987 (52 of 1987), the All India Council for Technical Education hereby makes the following regulations to amend the All India Council for Technical Education (Grant of approval for starting new technical institutions, introductions of courses for programmes and approval of intake capacity of seats for the courses or programmes) Regulations, 1994, namely :—

1. (1) These regulations may be called the All India Council for Technical Education (Grant of approval for starting new technical institutions, introducing of courses or programmes and approval of intake capacity of seats for the courses or programmes) Amendment Regulation, 1997.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the All India Council for Technical Education (Grant of approval for starting new technical institutions introduction of courses or programmes and approval of intake capacity of seats for the courses or programmes) Regulations, 1994 (hereinafter referred to as the said regulations), regulations 2 shall be re-numbered as sub-regulation (1) thereof, and after sub-regulation (1) as so re-numbered, the following sub-regulation shall be inserted, namely :—
 - "(2) These regulations shall not be applicable to the proposals relating to post graduate courses for Master of Business Administration or equivalent, Master of Computer Application or equivalent, and all post graduate courses in the field of technical education."
3. In the said regulations,—
 - (a) in regulation 3,—
 - (i) for clause (b), the following clause shall be substituted, namely :—
"(b) Bureau AIB" means the Bureau All India Boards of Studies of the council;
 - (ii) for clauses (d) and (e), the following clauses shall be substituted, namely :—
'(d) "Bureau RDII" means the Bureau of Research and Development Institute Interaction of the Council;
(e) "Bureau ET" means the Bureau of Engineering and Technology of the Council;'
 - (b) for the expressions "Bureau BOS", "Bureau RA" and "Bureau RC", wherever they occur, the expressions "Bureau AIB", "Bureau RDII", "Bureau ET" shall respectively be substituted.
4. In the said regulations in regulation 4, in sub-regulation (2), in clause (ii), the words "in respect of professional colleges" shall be omitted.
5. In the said regulations, in regulation 5,—
 - (a) in sub-regulation (1),—
 - (i) for the opening words "Forms application" the words "Forms of applicaton" shall be substituted;
 - (ii) after the words "seats in the courses", the words "or for obtaining a letter of viability" shall be inserted :
 - (b) in sub-regulation (2), after paragraph (c), the following paragraph shall be added, namely :—

"(f) An application for obtaining letter of viability from the Council for starting a new technical institutions shall be made in Form VI."

6. In the said regulations, in regulation 7, for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely :—

"(1) Every application for approval of the Council shall be submitted to in triplicate with a copy each to the concerned agencies as per the provisions of these regulations."

7. In the said regulations, for regulations 8 and 9, the following regulations shall be substituted, namely :—

"8. Scrutiny of Applications :—

- (1) On receipt of a copy of the application submitted to the Council for obtaining a letter of viability, the concerned University or the Directorate of Technical Education, having jurisdiction in the area in which the new technical institution is to be started, shall make arrangements for scrutiny and verification of the information contained therein.
- (2) If the University or the Directorate of Technical Education, as the case may be, desires to have a local inspection of the site, it may constitute its Local Inspection Committee (LIC) and under intimation to the applicant make such inspection of site.
- (3) On receipt of the report of the Local Inspection Committee or after verification of the particulars contained in the application to the satisfaction of the University or the Directorate of Technical Education as the case may be or by such other means as it may deem proper, it shall give its recommendations to the respective State Government or the University Grants Commission with a copy to the Council.
- (4) On receipt of the report containing the recommendations of the University or the Directorate of Technical Education, as the case may be, under sub-regulation (3), the State Government or the University Grants Commission, as the case may be, shall forward the report and its recommendations to the Council specifically dealing with the viability of the proposal having regard to the following requirements :—

(a). Requirement of Land :

The application shall identify suitable land for starting the new technical institution. The minimum requirement of such land shall be as indicated in Table I below :

Table I

Serial Number (1)	Locality (2)	Minimum Requirement of Land (Engineering and Technology) (3)	
		for Degree Level Institution (i)	for Diploma Level Institution (ii)
1.	Rural area	10 Hectares	8 Hectares
2.	Taluk or District Headquarters	4 Hectares	4 Hectares
3.	Metropolitan Cities or State Capitals	2 Hectares	2 Hectares

Note :—

It shall not be necessary for the applicant to have ownership or title of the land proposed to be utilised for starting the new technical institution at the stage of making the application in Form VI. The ownership or title shall be required only after issuance of the letter of viability.

(b) Funds

(i) The minimum requirement of funds for starting of new technical institution by a registered society/trust shall be as detailed in Table II below :

Table II

Serial Number (1)	Level of Engineering and Technology Institutions (2)	Minimum Fund required (3)
1.	Degree	Rs. 50 lakhs
2.	Diploma	Rs. 25 lakhs

Note:—

It shall not be necessary to produce any fixed money deposit receipt from a bank in the joint name of an applicant society/trust and the respective Regional Officer, at the stage of making an application in Form VI. This will be required only after issue of a letter of viability...

- (c) Notwithstanding anything contained in clauses (a) and (b), the requirement of land and funds in the case of new institutions in Architecture, Hotel Management and Catering Technology, Pharmacy and Applied Arts and Crafts shall be as per the relevant norms and standards specified by the Council in respect of such institutions.
- (d) Track record : Where the applicant is a registered society or trust it shall have a sound track record of running an educational institution for a minimum period of five years.
- (5) In respect of every application submitted to the Council on or before the 31st December, the concerned agencies, namely the concerned State Government, University or Directorate of Technical Education and the University Grants Commission, shall endeavour to forward their recommendations to it as expeditiously as possible so as to enable the Council to start processing the applications by the 28th February following.
- (6) Subject to the provisions of sub-regulation 9, the Regional Committee or the Board of Studies, as the case may be shall deliberate on the status of the various proposals and the recommendations of the State Government, University or the Directorate of Technical Education and University Grants Commission thereon and give its recommendations to the Council by March 31.
- (7) After considering the recommendations of the agencies concerned and after making such further enquiry as it may deem necessary, the Council may, by 15th April,—
 - (i) issue a letter of viability on the proposal to the applicant stating therein that the proposal is viable and that the applicant may proceed to take further action for getting final approval of the Council under these regulations : or
 - (ii) issue a letter of regret to the applicant stating therein the specific ground or grounds on which the application has been rejected :
Provided that no application shall be rejected unless the applicant has been given a reasonable opportunity of being heard in the matter.
- (8) While issuing a letter of viability under sub-regulation (7), the Council shall ask the applicant to submit by May 15 the following documents, along with the applications in Form I, namely :—
 - (i) (a) Deed of registration of land relating to ownership/title of the applicant society/trust on the land earmarked for setting up of the new institution;
 - (b) A land use certificate from the authority concerned; and
 - (c) In case the applicant is running any other educational institution in the same premises where the new institution is proposed to be set up, an irrevocable resolution of the applicant stating that sufficient area of the premises has been earmarked specifically for setting up the proposed institution.
 - (ii) A Fixed money Deposit jointly in the name of applicant society/trust and Regional officer of the respective Regional Office as per the requirements specified in Table II of sub-regulation (4) for a period of ten years after which the applicant may apply to the Council to allow or use the funds for development purposes of the institutions.
 - (iii) The accounts of the fund shall be maintained by the Regional Office.
 - (iv) In case the applicant society/trust does not hold ownership right over the land, a Lease Agreement duly registered in its name for temporary accommodation for a minimum period of two years along with lay out plan and photographs of the premises.
 - (v) A master plan for the entire institutional complex with the details of the plinth area, including area of laboratories, class rooms, drawing halls, workshops, library, administrative block, hostel etc. shall be submitted along with the construction schedule indicating estimated cost of construction involved.
 - (vi) A registered undertaking on non-judicial stamp paper, stating that the institute shall abide by all the regulations, Norms, Guidelines and Standards of the Council.
- (9) In case of applications for introduction of new courses or programme or for increase in the intake capacity of seats in any institution approved by the Council, the information about additional requirement of infrastructural and instructional facilities only shall be required to be furnished by May 15.
- (10) An Expert Committee appointed by the Chairman of the Council shall, at the cost of the applicant visit the premises of the proposed institution or existing institution, as the case may be, and verify all the details furnished in the application, prior to final approval being given.
- (11) The report of the Expert Committee and other relevant information obtained by the Council shall be placed before Executive Committee for its decision.

- (12) Subject to the provisions of sub-regulation (8), the final decision of the Council shall be communicated to the State Government concerned or the University Grants Commission, the University of the Directorate of Technical Education concerned, as the case may be, the Regional Office concerned and the applicant by 15th June in case the application was made before the preceding 31st December.
- (13) The rejection of an application shall not disentitle an applicant to make fresh application for any subsequent academic year.
- (14) The Council shall, in every year, before 31st December publish the names of approved technical institutions, University Departments or deemed Universities conducting courses in technical education, the courses and programmes approved by the Council and the number of seats permitted (annual intake capacity) for each course or programme and communicate relevant extracts of the same to the concerned authorities and agencies.
- (15) All institutions, courses and number of seats approved after publication of a list under sub-regulation (14) shall stand included in the relevant list.
- (16) The time schedule and sequences of processing applications for approved proposals shall be as given in the Schedule appended to these regulations :
 Provided that the Council may for good and sufficient reasons to be recorded in writing, modify the time schedule in respect of any class or category of applications.

9. Processing of application by bodies :—

- (1) The Council may process the various applications made under these regulations through its following bodies, namely :—
 - (a) Regional Committee concerned;
 - (b) Board of Studies concerned;
- (2) Before giving its recommendation on an application, the Regional Committee or the Board of Studies, as the case may be, may hold a meeting with the Secretary of the State Government dealing with technical education and the Director of Technical Education of the State Government, the Vice-Chancellor, a Director of Indian Institute of Technology, a member from the Executive Committee, nominee of the University Grants Commission, expert members nominated by the Chairman of the Council, Adviser Bureau ET, Adviser Bureau AIB, Regional Officer, Adviser Bureau Man Power, representative of Technical Bureau of the Ministry of Human Resource Development, Department of Education and any other special invitees.

9A. Returns to Central Government—The Council shall furnish a quarterly progress report to the Central Government indicating therein the progress of processing of applications by it for the periods ending the dates shown in column (3) of the Schedule appended to these regulations.”

8. In the said regulations, for the Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely :—

“SCHEDULE

[See regulation 8(13)]

TIME SCHEDULE AND SEQUENCE OF PROCESSING OF APPLICATIONS FOR APPROVAL

Serial Number	Stage of processing	Last date for completion of processing
(1)	(2)	(3)
1.	For receiving proposal by the Council at its Headquarters, the State Government, University Grants Commission, the University, Director of Technical Education and the Regional Office	31st December
2.	For receiving the comments from (i) the State Government, (ii) University Grants Commissions and (iii) the University or State Board/Directorate of Technical Education	28th February
3.	For consideration of the comments from the State Government, University Grants Commission, University or State Directorate of Technical Education by the Regional Committee or the Board of Studies concerned.	31st March

(1)	(2)	(3)
4.	For issue of letter of viability	15th April
5.	For receiving detailed proposals and documents from applicants as per letter of viability.	15th May
6.	Visit of the Council Expert Committee and report to the Executive Committee and for communicating the final decision to the State Government, the University Grants Commission, under intimation to the Director of Technical Education, the applicant, the University or State Directorate of Technical Education and the Regional office.	15th June."

9. In the said regulations, in Form I, under the heading "Instructions for submission of proposed for establishment of degree/diploma institution in engineering/technology/architecture, pharmacy, applied arts, etc." in paragraph 1, in sub-paragraph (a), for the figures, letters and word "31st December", the figures, letters and words "15th May, after issuance of the letter of viability" shall be substituted.

10. In the said regulations, in Forms I to V :—

- (i) For the words "Seven copies", wherever they occur, the words "Three copies" shall be substituted;
- (ii) under the heading "Appointment of Chairman of the Governing Body", the words "is a member of the Society/Trust" shall be omitted.

11. In the said regulations, after Form V, the following Form shall be added, namely :—

"FORM VI

[See regulation 5(2)(1)]

APPLICATION FOR ISSUE OF LETTER OF VIABILITY FOR STARTING NEW TECHNICAL INSTITUTION AT DEGREE/DIPLOMA LEVEL.

(PLEASE SEE THE TIME SCHEDULE AND PROCEDURE FOR PROCESSING OF APPLICATION ENCLOSED)

1. Name and address of the applicant (with Pin code)
(Trust/Society/Government/University/institution)
Fax No.
Telephone Number
STD Code
2. Registration Number and Date of registration of the applicant as a society/trust
3. Details of Members/Trustees and their experience in running educational/technical or other professional institutions.
4. Name and address of the proposed Institution
(with pin code)
(State clearly whether the proposed site falls within a Taluk/Dist. Headquarter/Metropolitan City/State Capital/other)
5. Type of technical Institution (Government/Private University, etc.) proposed to be started.
6. Name and address of the affiliating body
(University/State Board/Directorate)
7. Academic programmes proposed to be conducted from the academic year 19—19

Course title	Duration	Entry level	Degree or Diploma	Intake Capacity

Total :—

8. Track record of the applicant : Technical/Non-Professional Institutions run/managed by the Trust/Society : (Not for Government/University) (in case of Society/Trust only)

Name and address of the Institution	Courses conducted	Duration of each course	Level of studies	Intake capacity	Year of starting	Whether approved by AICTE/Univ./State Govt/Board

9. Land Area :

(a) Whether owned by the applicant Trust
Society/Institute or on lease basis.

owned———hectares.

lease———hectares.

(b) Land area proposed to be purchased by the Trust/Society/Institution :

———hectares.

10. Whether the applicant Trust/Society/institution submitted copy of proposal simultaneously to

(a) Central or State Government concerned

— Yes/No.

(b) University Grants Commission

— Yes/No.

(c) University/Board

— Yes/No.

(d) Regional Office of the Council

— Yes/No.

11. Availability of Funds

(enclose only copies of relevant proof)

(a) Fixed Deposits.

Rs.———Lakhs

(b) Funds available in Bank

Rs.———Lakhs

(c) Mobilisation of Additional Funds

Rs.———Lakhs

(d) Funds for meeting annual recurring expenditure

Rs.———Lakhs

12. Availability of built up space (in sq.m.) on permanent basis. ———hectares.

13. Availability of built up space (in sq.m.) on Temporary basis till permanent building is constructed. ———hectares.

14. Whether the applicant had at any time applied to All India Council for Technical Education before ? If yes, when and why was the proposal rejected ? Please give details

15. Any other information which the applicant may like to furnish in support of the proposal.

DECLARATION

I/We, on behalf of

undertake to comply with the norms and standards and regulations of the All India Council for Technical Education (Council). I do undertake to furnish the following documents, after receiving the viability letter within the stipulated period, failing which our proposal shall be liable to be rejected by the Council :—

- (1) Document showing ownership of land as per norms laid down by the Council, in the name of the society/trust/Applicant.
- (2) Fixed deposit receipts in joint name of Applicant and concerned Regional Officer, as per the norms laid down by the Council.

- (3) Master plan for permanent construction of the proposed technical institution along with estimated expenditure involved.
- (4) Lease deed/title deed of land for temporary accommodation having adequate area as per the norms laid down by the Council, in the name of Trust/Society/Applicant.
- (5) Any other relevant document the Council may ask for processing the proposal.

Place :

(Signature of the Applicant/Chairman/Secretary/Trustee/

Date :

Authorised signatory of the Trust/society)"

(Seal)

PROF. J. P. GUPTA, Member-Secy.

Footnote :—The principal Regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 23rd November, 1994 vide notification No. F-304-4/CCF/REG./94 dated the 31st October, 1994.

